भाजपा ने दिखलाई राज की गुंडागर्दी दलितों की पिटाई भी की और मीटिंग भी नहीं होने दी

रोहतक (म.मो.) दलित और पिछड़े सरकारी कर्मचारियों के संगठन 'बामसेफ़' का 20 वां राज्य स्तरीय अधिवेशन एमडी यूनिवर्सिटी के अम्बेडकर भवन में 15-16 अगस्त को होना तय हुआ था। इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अनेक प्रोफ़ेसर, इन्जीनियर और अन्य बुद्धिजीवी हिस्सा ले रहे थे। कार्यक्रम के लिये लॉ डिपार्टमेन्ट के पास स्थित अम्बेडकर भवन को बाकायदा लिखित अनुमति लेकर और फ़ीस भरकर, दो दिन, यानि 15 और 16 अगस्त 2015 के लिये बुक कर लिया गया था। नियत समय से कुछ पहले 10-15 लोग हॉल में अधिवेशन की तैयारी के लिये पहुंच चुके थे। बाकी कुछ लोग बाहर कार्यक्रम शुरू होने के इन्तज़ार में टहल रहे थे। लेकिन उनको अनुमान नहीं था कि 15 अगस्त का यह स्वतंत्रता दिवस प्रशासन और पुलिस की गुलामी का कैसा नज़ारा उनके सामने प्रस्तुत करेगा।

सम्मेलन का उद्घाटन एसपी परिहार ने करना था, मुख्य अतिथी लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर डॉ. डी एन एस यादव थे तथा वक्ताओं में कई प्रासेफ़ेसरों के अलावा जाने-माने चिन्तक और लेखक अनिल चामड़िया भी थे। लेकिन ये महान विचारक, चिन्तक व लेखक अपने विचार प्रकट करते उसके पहले संघ, भाजपा और इनके छात्र संगठन के 10-15 लोग अपने विचार प्रकट करने आ गये। इन लोग़ों ने आकर हॉल के गेट पर ताला लगा दिया। ये लोग वन्देमातरम के नारे लगा रहे थे और बामसेफ के लोग़ों को देशद्रोही बता रहे थे। क्योंकि बामसेफ एक पूरी तरह से कानूनी संगठन है और उन्होंने कार्यक्रम के लिये हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था इसलिये यूनिवर्सिटी से सम्पर्क किया और ताला खुलवाने की प्रार्थना की। वहां मौजूद पुलिस से भी अनुरोध किया गया कि वो ताला खुलवायें, क्योंकि अन्दर 15-20 लोग बन्द हैं। लेकिन वहां मौजूद एसएचओ ने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था का है ताला खुलवाने का नहीं। यही पुलिसवाले ताला तोड़ने में अपनी जी जान लगा देते अगर अन्दर वीसी या कोई अन्य अधिकारी बन्द होता। सरेआम 342 आईपीसी का अपराध हो रहा था पर पुलिस खामोश रही।

यूनिवर्सिटी से आये रजिस्ट्रार ने काफ़ी देर तक कभी संघी निक्कारों से तो कभी बामसेफ वालों से बात-चीत का ढोंग किया। होना तो यह चाहिये था कि रजिस्ट्रार आते ही पुलिस मदद लेकर ताला खुलवा देता और बदमाशों को गिरफ़्तार करवाता। लेकिन इतना न्यायप्रिय होता तो वह रजिस्ट्रार ही कैसे बनता। वहां तक पहुंचने के लिये तो बेशर्मी और चाटुकारिता ही एकमात्र काबलियत जो ठहरी।

खैर प्रशासन और पुलिस की मदद से चल रहे इस नाटक से तंग आकर व देर होती देख बामसेफ़ ने खुद ही ताला खोलकर अन्दर बन्द अपने साथियों को मुक्त करवाने का फ़ैसला किया। लेकिन खट्टर के राज में शुद्र लोग संघी निक्करों को कुछ कहें ये पुलिस को कहां मंजूर था सो बामसेफ़ वालों पर लाठी चार्ज कर दिया गया। लाठी चार्ज में कई महिलाओं सहित लगभग 10-12 लोग़ों को चोटें आई। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन 10-15 संघियों व भाजपाईयों की पुलिस ने पूरी सुरक्षा की जो गैरकानूनी रूप से एक सरकारी भवन पर ताला लगाये बेठे थे। अब कल को कोई संघी आकर आपके घर पर ताला लगाकर बैठ जाये तो आप क्या करेंगे ये आप सोचिए क्योंकि ये पुलिस का तो काम अब रहा नहीं।

खबर मिलने पर पुलिस के एस पी साहब भी और पुलिस बल लेकर इस 'स्वतंत्रता संग्राम' में हिस्सा लेने पहुंच गये। खैर उन्होंने आकर इतनी समझदारी का काम किया कि हॉल का ताला खुलवाकर अन्दर बन्द बामसेफ के लोग़ों को बाहर निकलवा दिया। लेकिन इसी बीच रजिस्ट्रार महोदय ने यह रहस्योद्घाटन कर दिया कि कल ही भाजपाई संगठन एबीबीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्) द्वारा एक पत्र दिया गया था कि ये कार्यक्रम करने वाले लोग देशद्रोही हैं। हमारे देवताओं और संस्कृति का अपमान करते हैं इसलिये इनको यहां कार्यक्रम करने की अनुमति न दी जाये। लिहाज़ा उन्होंने बामसेफ को दी अनुमति कल ही वापिस ले ली थी। इसलिये उनको (बामसेफ को) यह कार्यक्रम कहीं और करना होगा।

मतलब अब आगे से सभी संगठनों को कोई कार्यक्रम करने के लिये संघियों से देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है।

बामसेफ वालों ने अपना कार्यक्रम तो किसी तरह रोहतक के खोखराकोट स्थित अम्बेडकर स्कूल में पूरा कर लिया लेकिन इस घटना में छिपे अर्थों को वे कितना समझ पाये कहना मुश्किल है। इस घटना ने दिखा दिया कि संघी विचारधारा में दलितों का स्थान आज भी शूद्रों की तरह ही है। हां वोटों के लिये उन्हें भरमाने के लिये वे अम्बेडकर के जन्मदिन समारोह जरूर मनायेंगे! करोड़ों खर्च करके भारत की संघी सरकार लंदन में अम्बेडकर का मकान खरीदेगी। बड़ी विडम्बना है कि एक तरफ़ तो भाजपा महाराष्ट्र और गुजरात में उनकी किताबों पर प्रतिबन्ध लगा रही है और दूसरी तरफ़ अम्बेडकर का जन्मदिन समारोह! यानी दलित मुक्ति के तुम्हारे विचार जायें कूड़े में बस हमें तो तुम दलितों के वोट दिलाने का काम करो। शायद इसी पर विचार करने के लिये बामसेफ़ ने बहस का एक विषय यह भी रखा था-कांग्रेस व भाजपा बाबा की 125 वीं जयन्ती मनाने पर मजबूर क्यों?

लेकिन बामसेफ़ को यह समझना चाहिये कि दलितों को अगर एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज दिलाना है तो उन्हें अन्य प्रगतिशील ताकतों के साथ मिलकर आगे बढना होगा वरना सिर्फ़ आरक्षण के लिये लड़कर तो वे अपने में से कुछ और ब्राह्मण ही पैदा करेंगे। बता दें कि इस घटना के बारे में जब रोहतक के आईजी पुलिस श्रीकान्त जाधव से जानकारी मांगी गई तो वो इस पूरी घटना से अनभिज्ञ थे। आईजी महोदय खुद दलित वर्ग से हैं। जब वही दलितों के एक जागरूक संगठन के कानून प्रदत्त अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके तो आम दलित की तो क्या करेंगे। वे तो सिर्फ़ शासक वर्ग की ही मदद करेंगे। ये सब दलितों से पैदा हुये नव ब्राह्मण है।

इस घटना में छुपी फ़ासिज़्म की दस्तक और खट्टर के गुरू मोदी के हिटलरी स्वरूप की छाया को पहचान लेना चाहिये। जान लेना चाहिये कि कल मुस्लिमों को देशद्रोही बताकर मारा गया, आज दलितों को देशद्रोही बताया जा रहा, तो कोई आश्चर्य नहीं कि कल जाटों, गूजरों आदि को भी उत्पाती, विद्रोही और फ़िर देशद्रोही घोषित कर उन पर हमला कर दिया जाये।

एतिहासिक विडम्बनायें

जापानी विडम्बना

दूसरे विश्वयुद्ध का निर्णय वास्तव में 10 मई 1945 को ही हो गया था जब रूसी फ़ौजें हिटलर को वापिस खदेड़ते हुये यूरोप में प्रवेश कर गयी थी। तब तक रूस की लाख अपीलों के बावजूद अमरीका ने जर्मन फ़ौजों के खिलाफ़ कोई लड़ाई नहीं शुरू की। एक तरह से जर्मनी की फ़ौजों को रूस ने अकेले अपने दम पर परास्त किया। लेकिन युद्ध में आये इस निर्णायक मोड़ के बाद अमरीका एकदम से सक्रिय हो गया। उसने न सिर्फ़ नार्मण्डी शहर में रूसी फ़ौज़ों से आगे अपने छाताधारी सैनिक उतार कर कब्ज़ा कर लिया बल्कि 6 और 9 अगस्त को जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकि पर परमाणु बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। स्पष्ट रूप से यह बम लड़ाई जीतने के लिये नहीं गिराये गये थे क्योंकि वह तो तब तक निर्णायक रूप से रूस जीत ही चुका था। ये बम गिराने के पीछे दो कारण थे। एक पहली बार हासिल इस नयी तकनीक-परमाणु बम-का परीक्षण करना और दूसरा इस नयी हासिल ताकत के प्रदर्शन से रूस को डराना। परमाणु बम की इस विभिषिका को देखते हुये जापान ने कभी भी परमाणु उर्जा का युद्ध में उपयोग न करने का निर्णय लिया।

लेकिन विडम्बना देखिये कि जिस अमरीका ने जापान को तबाह किया आज वह उसी के साथ खड़ा है और उसी की छत्र छाया में उस पूंजीवादी व्यवस्था का गढ़ बना हुआ है जिसने दूसरा विश्वयुद्ध छेड़ा और जापान को तबाह किया। क्या जापानियों को इस पूंजीवादी व्यवस्था व इसके ध्वजवाहक अमरीका को उखाड़ नहीं फेंकना चाहिये था।

दूसरी घटना मुस्लिम समुदाय से सम्बन्धित है। 1987 में पूरे भारत में एक विज्ञान प्रचार जत्था निकाला गया था। उत्तरी भारत में इस जत्थे की शुरूआत 2 अक्टूबर को कश्मीर विश्वविद्यालय से की गयी थी। जब इस अवसर पर एक फ़िल्म वहां विश्वविद्यालय के प्रेक्षाग्रह में दिखायी गयी तो दर्शको में मौजूद सभी मुस्लिम नवयुवकों ने इसका पुरज़ोर विरोध किया। क्योंकि वह फ़िल्म न्यूक्लीयर हथियारों में कटौती के बारे में रूस और अमरीका के बीच हुयी बात-चीत के बारे में थी जिसमें आंकड़े और सबूत देकर यह बताया गया था कि किस तरह अमरीका इन हथियारों में कोई कटौती करने को तैयार नहीं था। जबकि रूस ने उसकी हर तरह की उल्टी सीधी शर्तें मान ली थी ताकि दुनिया से नाभिकीय हथियारों को खत्म किया जा सके। इन नवयुवकों को मानना था कि अमरीका तो सारी दुनिया में सभी धर्मों के लोग़ों का व उनके अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है!

लेकिन विडम्बना देखिये कि आज उसी कश्मीर यूनिवर्सिटी या कश्मीर घाटी में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुस्लिम अमरीका को अपना व सभी लोग़ों के जनतांत्रिक अधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। समझ ने क्या करवट ली है! लेकिन अभी भी वे यह समझने में नाकामयाब रहे हैं कि यह अमरीका नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसका अमरीका आज सबसे बड़ा पुरोधा है, जिसका विरोध करने की जरूरत है क्योंकि सभी लोग़ों के जनतांत्रिक अधिकारों की यही विरोध सबसे बड़ी गारंटी है ।

आरक्षण-रिश्वत की मलाई के लिये लड़ाई ?

पहले गूजर, फ़िर जाट और मराठा और अब गुजरात में पटेल आरक्षण के लिये आंदोलन का झण्डा उठाये हुये है। मज़ेदार बात यह भी है कि इन सभी जातियों के पास बड़ी-बड़ी रैली करने के संसाधान हैं यानी पैसा है। तोड़-फ़ोड़ करने का माद्दा है, जातिगत घमण्ड है फ़िर भी मांग है पिछड़ों में शामिल किये जाने की। इसमें पटेल तो वो समुदाय है जो पूरे एनआरआई गुजराती समुदाय का आधा हिस्सा है और जिसके चार-चार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र व हरियाणा में भी क्रमश: मराठों व जाटों के कई मुख्यमंत्री रहे हैं। और गूजरों के हर सरकार में मंत्री हैं-केन्द्र में व राज्य सरकारों में। फ़िर भी वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो क्यों?

स्पष्ट है कि यह मांग कोई देशभक्ति के लिये नहीं है। इन लोगों में एक तबका तो उन गरीबों का है जो किसी तरह जीवनयापन के लिये एक नौकरी चाहते हैं लेकिन इसके नेतृत्व में वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी में मिलने वाली रिश्वत की मलाई में अपना हिस्सा चाहते हैं।

अगर सरकारी कर्मचारियों विशेषकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस व कॉलेज़ों के प्राध्यापकों की तनख्वाह आधी कर दी जाये और उनसे काम ठोक के लिया जाये तो आधे तो मौजूदा कर्मचारी ही नौकरी छोड़ भाग खड़े होंगे, आरक्षण तो मांगेगा ही कौन। ये रिश्वत की मलाई के लिये झगड़ रहे लोग हैं जो मोदी के 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' के दावे की कलई खोल रहे हैं।

-अजातशत्रु

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 16-31 अगस्त 2015 का अंक मिला जिसमें अनेक महत्वपूर्ण लेख-पढने को मिले। लेख 'वोट जुटाऊ से कटाऊ बन गए नरेन्द्र मोदी साम्प्रदायिकता पड़ी भारी: विकास-कलई उतरी' के जरिए नरेन्द्र मोदी की साम्प्रदायिक राजनीति का तर्क संगत खुलासा किया गया है।

नरेन्द्र मोदी को संघ परिवार द्वारा विकास के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है तो मोदी ने भाजपा व संघ परिवार को साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने व साम्प्रदायिक राजनीति का खेल खेलने की खुली छूट दे रखी है तथा जो हिंदू कट्टरपंथी विभिन्न आतंकवादी कांड में अदालतों के चक्कर में फ़से हुए हैं उनको रिहा करने के लिये सरकार ने सरकारी गवाह तोड़कर, अभियोजकों पर दबाव डालकर केस कमज़ोर करके, दोषियों की जमानतें कराके उनके विरुद्ध तमाम मामलों को रफ़ा-दफ़ा करने का अभियान चला रखा है। इस अभियान में जांच एजेंसियां मोदी सरकार का हर सम्भव तरीके से सहयोग कर रही है। समझौता एक्सप्रेस कांड के प्रमुख अभियुक्त असीमानंद को जमानत दिलाकर उसकी जमानत के विरुद्ध राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुखिया द्वारा अपील ना करने के निर्णय ने मोदी सरकार की मंशा को स्पष्ट उज़ागर कर दिया है। इसी तरह अन्य मामलों जैसे मालेगांव बम कांड, हैदराबाद मक्का मस्जिद कांड, अजमेर शरीफ कांड आदि में लिप्त कट्टर हिंदू आतंकवादियों को भी रिहा कराने के प्रयास ज़ारी है। स्पष्ट है कि इस कार्य में जो भी अधिकारी सरकार से सहयोग करेंगे उनको किसी न किसी प्रकार से पुरस्कृत किया जाएगा तथा जो अधिकारी सरकार से सहयोग नहीं करेंगे उनको दण्डित किया जाएगा। इसका ज्वलंत उदाहरण है गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की भारतीय पुलिस सेवा में 27 वर्ष की सेवा के बाद नौकरी से बर्खास्तगी। संजीव भट्ट का कसूर केवल इतना है कि उसने गुजरात दंगों (2002) की जांच के लिये स्थापित नानावती आयोग तथा ज़ाकिया जाफ़री की शिकायत पर जांच के लिये गठित सिट (एसआईटी) में गवाही दी थी। इसके अतिरिक्त संजीव भट्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हल्फनामा दिया था जिसमें उसने कहा था कि गोधरा रेल गाड़ी कांड के बाद 27 फरवरी 2002 को मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सरकारी निवास पर आयोजित बैठक में उच्च पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दें। मोदी सरकार अपने एक अधिकारी की स्पष्ट वादिता और उसके साहस को अपने विरुद्ध कैसे सहन करेगी? गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार पर भारत सरकार मुस्लिम आतंकवादी हाफ़िज सईद को बचाने का आरोप लगाती है तो अब पाकिस्तान सरकार समझौता कांड के दोषी हिंदू आतंकवादी असीमानंद को बचाने का भारत सरकार पर आरोप लगाती है। स्पष्ट है कि दोनों देशों की सरकार अपने-अपने धर्म से संबन्धित आतंकवादियों के विरुद्ध मुकदमों को रफ़ा-दफ़ा कर बचाने का प्रयास कर रही है। धर्म के नाम पर आम जनता को हो रही परेशानी पर लेख 'हे शिव! ये तुम्हारे कांवड़ धारी भक्त!' तथा 'कांवड़गर्दी पर अंकुश का प्रयास एक मज़ाक बन कर रह गया' समीचीन है। डाक कांवड़ के नाम पर ट्रकों में लदकर उछल-कूद मचाते व ऊंची आवाज़ में डीजे बजाते हुए चलकर सड़क यातायात को बाधित कर देते हैं तथा इन यात्रियों की सेवा के लिये लगे हुए शिविरों में भी डीजे ऊंची आवाज़ में बजाए जाते हैं। सरकार ने इनको नियमित करने का प्रयास किया तो अनेक हिंदू संगठन इनके बचाव पर आ गये। माता की चौकी तथा जगराता के नाम पर सड़क पर शामियाना लगाकर रास्ता बंद कर देना और रात भर डीजे का ऊंची आवाज़ में बजना आम बात हो गई है, इससे चाहे किसी को परेशानी होती हो। जैन धर्म में संथारा (एक प्रकार की आत्महत्या) को उच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी घोषित करने के निर्णय का जैन समाज विरोध कर रहा है तो इस विरोध में उनका साथ विश्व हिंदू परिषद्, बजरंग दल, मंदिर बचाओ संघर्ष समिति, देवस्थान महासभा आदि भी दे रहे हैं। 'राधे मां' के विरुद्ध शिकायतों के संदर्भ में चलाए जा रहे मुकदमों का विरोध हिंदू महासभा कर रही है। गौरतलब है कि ये हिंदू धार्मिक संगठन आरोप लगाते हैं कि हिन्दू संतों पर मुकदमें चलाकर हिंदू संतों को बदनाम करने की साजिश हो रही है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा महाराष्ट्र की मंत्री पंकज़ा मुण्डे के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के संदर्भ में संसद में हुए पूरे नाट्य क्रम के दौरान सुषमा स्वराज द्वारा अपने बचाव में दिए गए भाषण के दौरान कांग्रेस पर उसके पिछले भ्रष्टाचार कांड मामलों पर लगाए गए आरोपों के औचित्य पर लेख 'मां-पिता से पूछो' मासी से नहीं...' में तर्क संगत विवेचन किया गया है।

स्तम्भ खबर दार में 'बड़का झूठा पार्टी-नितीश' मोदी द्वारा झूठ बोलने तथा दूसरी पार्टियों पर व्यंग्य करने की आदत के कारण नितीश द्वारा भजपा को बड़का झूठा पार्टी कहने पर काल्पनिक साक्षात्कार के जरिए मोदी व नितीश दोनों की नीतियों पर उचित व्यंग्य किया गया है।

लेख 'समाज की पशुवत प्रवृत्तियों का प्रतीक है मृत्युदंड' में मृत्युदण्ड व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में ठोस तर्क संगत प्रयास है। एक सर्वे के अनुसार मृत्युदण्ड पाने वालों में भारी बहुमत वंचित, दलित व अल्पसंख्यकों का है जबकि सम्पनशील तथा उच्च वर्गों के लोग़ों की संख्या कम है। इसलिये मृत्यु दण्ड की वयवस्था समाप्त होनी चाहिये।

स्तम्भ तुर्की-ब-तुर्की में 'अमित शाह भला मुंह कहां छिपाय' के जरिए गया में बिहार विधान सभा के दौरान लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला में सज़ा को लेकर नरेन्द्र मोदी द्वारा लालू का उपहास करते हुए की गई टिप्पणी के दौरान अमितशाह का जघन्य अपराधों में जेल में रहने की घटनाओं को भूलना तथा शिवराज सिंह चौहान व वसुंधरा राजे को विभिन्न घोटालों में लिप्त होने के बावजूद कार्य कुशलता का प्रमाणपत्र देने तथा अमित शाह के कारनामों का तर्क संगत विश्लेषण किया गया है। अन्य सभी लेख उच्च स्तरीय तथा प्रशंसनीय है।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता